



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-08012025-260022
CG-DL-E-08012025-260022

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 91]

नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 3, 2025/पौष 13, 1946

No. 91]

NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 3, 2025/PAUSHA 13, 1946

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय

(सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 जनवरी, 2025

का.आ. 93(अ).—केंद्रीय सरकार, हाथ से मैला उठाने वाले कर्मियों के नियोजन का प्रतिषेध और उनका पुनर्वास अधिनियम, 2013 (2013 का 25) की धारा 29 की उप-धारा (1) और (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 13 जनवरी, 2014 की संख्यांक का.आ. 89 (अ) द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग की अधिसूचना में फिर से निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना में पैरा च में -

- (i) राज्य शीर्षक के अंतर्गत, मद संख्यांक (iv) और (vi) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात्:-

“(iv) हरियाणा

(vi) बिहार”

- (ii) संघ राज्य क्षेत्र शीर्षक के अंतर्गत, मद संख्यांक (vii) और उससे संबंधित प्रविष्टि के स्थान पर “(vii) अंडमान और निकोबार द्वीप समूह” प्रविष्टि रखी जाएगी।

[फा. सं. यू-19014/10/2021-प्लान-भाग (1)]

योगिता स्वरूप, वरिष्ठ आर्थिक सलाहकार

नोट:- मूल अधिसूचना दिनांक 13 जनवरी, 2014 की संख्या का.आ. 89 (अ) के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित की गई थी तत्पश्चात्, इसमें दिनांक 28 फरवरी, 2014, का.आ. 605 (अ), दिनांक 07 अगस्त, 2014, का.आ. 2008 (अ), दिनांक 16 फरवरी, 2017, का.आ. 476 (अ), दिनांक 02 मई, 2017, का.आ. 1389 (अ), दिनांक 01 मार्च, 2018, का.आ. 888 (अ), दिनांक 26 जुलाई, 2023, का.आ. 3338 (अ), दिनांक 09 अक्टूबर, 2023, का.आ. 4379 (अ), और दिनांक 21 मार्च, 2024, का.आ. 1510 (अ) द्वारा संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF SOCIAL JUSTICE AND EMPOWERMENT

(Department of Social Justice and Empowerment)

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd January, 2025

S.O. 93(E).— In exercise of the powers conferred by sub-section (1) and (2) of section 29 of the Prohibition of Employment as Manual Scavengers and their Rehabilitation Act, 2013 (25 of 2013), the Central Government hereby makes the following further amendments to the notification of the Government of India in the Ministry of Social Justice and Empowerment, Department of Social Justice and Empowerment, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3 Sub-section (ii), vide number S.O. 89 (E), dated the 13th January, 2014, namely:-

In the said notification, in paragraph F, –

- (i) under the heading States, for item numbers (iv) and (vi) and the entries relating thereto, the following entries shall respectively be substituted, namely: –

“(iv) Haryana,

(vi) Bihar”;
- (ii) under the heading, Union Territory, for item number (vii) and the entry relating thereto, the entry “(vii) Andaman and Nicobar Islands” shall be substituted.

[F. No. U-19014/10/2021-PLAN-Part (1)]

YOGITA SWAROOP, Senior Economic Advisor

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii), vide number S.O. 89 (E), dated the 13th January, 2014 and subsequently amended vide numbers S.O. 605 (E), dated the 28th February, 2014, S.O. 2008 (E), dated the 7th August, 2014, S.O. 476 (E), dated the 16th February, 2017, S.O. 1389 (E), dated 2nd May, 2017, S.O. 888 (E), dated the 1st March, 2018, S.O. 3338 (E), dated the 26th July, 2023, S.O. 4379 (E), dated the 9th October, 2023 and S.O. 1510 (E), dated the 21st March, 2024.